or agreed to, for irrigation projects in the country and, secondly, the names of the projects in Andhra Pradesh receiving credit or assistance from the International Development Agency and the total amount of assistance or credit given or agreed to be given to these projects

MR. SPEAKER: This is about the Godavari project.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: It comes from the original question.

SHRI KEDAR NATH SINGH: For the World Bank we have suggested nine projects—one in Bihar, one in Gujarat, one in Karnataka, one in Kerala, three in Maharashtra and one in Orissa.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: Sir, he is evading my question

MR. SPEAKER: I just kept quiet. It is not a relevant question.

SHRI KEDAR NATH SINGH: There are two more projects one in Gujarat and one in Andhra Pradesh.

SHRI P. NARASIMHA REDDY: The Minister has been pleased to inform the House that the World Bank loan is adjusted towards the Central Pool and that it is not related to any particular project. May I know in this connection whether the actual release of the World Bank loan depends upon the pace of utilisation as evidenced by the execution of the project and, if so, is it not in the interests of the country that the pace of the execution of the project should be stepped up so that the loans sanctioned by the World Bank may be fully utilized to the benefit of the Central pool?

SHRI KEDAR NATH SINGH: We are taking all the steps to get them completed quickly. But the execution depends entirely on the State Governments. We are all trying to see that the projects are completed in time.

MR. SPEAKER: The question was very simple. If the release of the loan depends upon the completion of the various stages of the project, will it not be better to complete them quickly? It is a suggestion for action.

SHRI KEDAR NATH SINGH: Thank you.

MR. SPEAKER: It is not always my job to invite attention to that

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: The hon. Minister in his earlier reply said that certain projects have been selected for World Bank assistance. In this connection, may I know from him whether the identification of these projects for World Bank assistance is made on the basis of accelerating the completion of the projects which have got a long gestation period or they have been selected at random?

SHRI KEDAR NATH SINGH: I may inform the House that the selection of projects is based on their utility. The opinion is taken of the State Government and the Central Water and Power Commission. On this basis, the projects are selected.

Non-payment of Sugarcane price by Sugar Mills in U. P. and Bihar

*467. SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that in Uttar Pradesh and Bihar the sugar mill owners are not paying the current sugarcane price inspite of Government orders and thus crores of rupees are in arrears and if so, the reaction of the Government; and

(b) how much arrears of the last season are still outstanding?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAHNAWAZ

KHAN): (a) The sugar factories in U.P. and Bihar are paying the current sugarcane prices. A statement showing the arrears of cane prices during the current season as on 15th February 1975 is laid on the Table of the House. The State Governments are taking all possible steps, including legal action wherever necessary, to get the arrears cleared

(b) The cane price arrears relatable to 1973-74 season as on 15th February 1975 were:—

Rs 143.14 lakhs in Uttar Pradesh and

Rs. 21.82 lakhs in Bihar.

Statement

(Fugures in Lakh Rs)

State	Total Price due for cane purchased during 1974-75 upto 15th Feb. 1975	Cane price paid upto 15th Feb. 1975	Balance cane price due 15-2-75
Uttar Pradesh	10585 68*	9040 61	1545 07
Bihar	2390 77*	1467 34	923 43

* Includes price payable for cane purchased during the first for night of February 1975 to the extent of Rs. 1984 lakhs in Uttar Pradesh and Rs. 527 lakhs in Bihar, for which time upto 14 days from the date of delivery is normally allowed under the rules

श्री नरसिंह नारायण पांडे : माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि 15 फरवरी, 1975 तक उत्तर प्रदेश और बिहार मे किसानों का 24 करोड रुपया बकाया है। पिछले सीजन और उस से पिछले सीजन का भी 7 करोड रुपया बकाया है। क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आप के आदेशों के बावजूद तथा कैन-कन्ट्रोलर एक्ट के तहत आदेशों के बावजूद कि 14 दिनो के अन्दर किसानों को गन्ने के दाम का भुगतान हो जायगा, यह भुगतान क्यों नही किया गया तथा इन के खिलाफ सरकार ने क्या कानूनी कार्यवाही की है, क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है?

मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करें क्या शुगर मिल मैंनेजर्स यह दबाव डाल रहे हैं कि या तो रिजर्व बैंक क्रैडिट-स्कीम की पालिसी को रिवाइज करके 200 रुपया क्विंटल लेवी दे शुगर पर हम को या जो लेवी शुगर प्राइस को रिवाइज किया जाय या जो 35 परसेन्ट फ्री शुगर दे रहे हैं उसको बढ़ाया जाय? क्या इस तरह का दबाव डाला जा रहा है जिसके कारण पेमेन्ट करने के आप के कायदे-कानूनों का पालन प्रान्तीय सरकार जिला स्तर पर नही कर पा रही है?

श्री शाहनवाज खां : मैं ने अर्ज किया है कि इस रकम मे फरवरी के पहले दो हफ्ते तक की रकम शामिल है और दो हफ्ते का पेमेन्ट डिले करने का उन को हक है। अगर इस को निकाल दिया जाय तो यू० पी० के केन के पेमेन्ट का कुछ भी बकाया नही रह जाता है। इसी तरह से बिहार मे भी करेन्ट सीजन का पेमेन्ट बहुत अच्छा है। जहां तक पिछले सीजन्स का ताल्लुक है 1973-74 और 1972-73 और उस के भी पहले के लगभग 6 करोड रुपया किसानो का बाकी है। सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी यह रुपया किसानों को मिल जाय। कम्परेटिवली 6 करोड रुपया ज्यादा रकम नही है, लेकिन यह रुपया भी किसानो को जरूर मिलना चाहिये गवर्नमेन्ट इस के लिये

कोशिश कर रही है कि किसानों का जो भी रुपया बकाया है, वह जल्द से जल्द बेबाक हो जाय। जो मिलें पेमेन्ट नही कर पा रही है या जहां पर मिल नही चल रही हैं, स्टेट गवर्नमेन्ट उन मिलों का कान्ट्रोल अपने हाथ में ले रही है।

यह सही है कि इस साल फैक्ट्रीज के मालिकों ने मांग की है कि जो क्रेडिटज फैसलिटी उन्हें दी जा रही है, वह ना काफी है। उन की यह शिकायत किसी हद तक हकबजानिब है। मेरी मिनिस्ट्री ने फाइनेन्स मिनिस्ट्री से बात की है और कहा है कि रिजर्व बैंक क्रैडिट फैसिलिटी बढ़ा सकता है तो वह इस मामले की जांच करे।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : क्या यह बात सही है कि कि शुगर मिल्ज के अन्दर 1 मिलियन टन चीनी पड़ी हुई है जो एक्सपोर्ट के लिये है और पोर्ट पर पैसेज न मिलने के कारण बाहर नही भेजी जा रही है। क्या सरकार इस को जल्द भेजने की व्यवस्था करेगी जिस से फौरन एक्सचेन्ज मिल सके और किसानों का तथा दूसरे बकायों का पेमेन्ट हो सके? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो फिगर्स यहां सप्लाई की है- क्या वे इस की फिर से जांच करायेंगे क्योंकि इण्डियन शुगर मिल्स एसोसियेशन ने स्वयं अपने रिप्रेजेन्टेशन के तहत खाद्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से कहा है कि 50 करोड़ रुपया तो केवल यू० पी० में गन्ने का किसानों का बकाया रह जायगा, यदि वह फैसिलिटि जिस का मैंने अभी जिक्र किया है उन को न दी गई। अगर यह बात सही है तो क्या आप उन की फिगर को देखते हुए अपनी फिगर्स की जांच करायेंगे?

अध्यक्ष महोदय : आप के सवाल करने का तरीका बहुत अजीब है खुद ही फिगर्स देते है और खुद ही पूछते हैं कि क्या यह सही है?

श्री नर सिंह नारायण पांडे : मैं तो इन्फोरमेशन दे रहा हूं।

MR. SPEAKER: A Member can ask for information and not give information.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: I am giving the information on the basis of the representation which was made by the Sugar Mills Association. I am asking whether it is true or not.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: It is true. The position is this. This House would be glad to know that, at present, the sugar mills in the country have produced over six lakh tonnes in excess of what they had produced last year during the corresponding period and we are going to produce more. We hope, this year, we will be in a position to offer about one million tonnes for export, if there is no difficulty in securing shipping space.

MR. SPEAKER: This information which he has given to you, you should have given to him.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Is the Government considering to accept the second demand made by the Sugar Mill—Owners' Association in their Memorandum, namely, that the proportion of free sale sugar should be increased from 35 per cent to a higher figure?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: Government have no intention of accepting this.

श्री तारकेश्वर पांडे : जब करोड़ों रुपये की चीनी मिलों में जमा है और अब तक विदेश नही भेजी जा सकी है, क्या आप इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि आप खुद उस चीनी को जब्त कर के और बेच कर किसानों का बकाया अदा करदे? ऐसा पहले भी हुआ है क्या इतनी हिम्मत आप रखते हैं?

श्री शाहनवाज खां : हकूमत हिम्मत तो रखती है, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे प्रोडक्शन मे बाधा पड़े।

श्री तारकेश्वर पांडे : इससे प्रोडक्शन में बाधा नहीं पड़ती है श्रीमन्

श्री राम रतन शर्मा : किसानों को गन्ने का उत्पादक मूल्य न मिलने के कारण गन्ने का उत्पादन हर साल कम होता जा रहा है। अभी मंत्री महोदय ने यह माना है कि उत्तर प्रदेश में ही लगभग 1 करोड़ रुपये से ऊपर 1974-75 का मिल मालिकों को गन्ना उत्पादकों को देना बाकी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो रुपया गन्ना मिल मालिकों ने किसानों को नहीं दिया उन के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की वसूली के लिये ?

श्री शाहनवाज खां : मैं ने जैसा कहा है बहुत सारी मिल्स तो सरकार ने अपने कब्जे में ले ली हैं यू० पी० करीब में, 13 मिल्स ली हैं।

SHRI R. R. SHARMA: I wanted to know what legal action they have taken. Have they arrested the owner of any defaulting mills?

श्री शाहनवाज खां : कानूनी कार्यवाही मिलों के खिलाफ करना स्टेट गवर्नमेंटस की जिम्मेदारी होती है। मैं इस की जानकारी इकट्ठी कर के दूंगा।

श्री डी० एन० तिवारी : गत मास मुझे अपने क्षेत्र में जिसमें 5 शुगर फैक्ट्रीज हैं, भ्रमण करते मुझे मालूम हुआ कि महीनों से किसानों का बकाया पड़ा हुआ है और उसकी वसूली के लिये न प्रान्तीय सरकार ने और न आपने हः कोई कार्यवाही की है, और न उन मिलों पर कोई केस चला है और न नोटिस दिया गया है। तो आपके और शुगर फैक्ट्रीज ओनर्स के बीच जो भी संघर्ष हो उसके लिये किसानों को क्यों पीड़ित किया जाय, क्यों न उनको दाम दिलाया जाय ? 50 करोड़ रु० किसानों का बाकी रहे तो वह अपने बाल बच्चे कैसे पालेंगे ? आज तक कभी किसी मिल ओनर पर कोई केस चला है ? यदि हां, तो बिहार और यू० पी० में कितने केसेज चले हैं क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा बकाया है ?

श्री शाहनवाज खां : कार्यवाही कई जगहों पर की गई है। अलग अलग मेरे पास इस वक्त इत्तिला नहीं है।

श्री डी० एन० तिवारी : अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

PROF. MADHU DANDAVATE: I hope the hon. Minister has gone through the Bhargava Commission report. If so, is it not a fact that one group of the Bhargava Commission has recommended nationalisation of the sugar industry on the specific plea of bad factory-farmer relationships and the inordinate delay in cane price payment? In view of this, when they have insisted on nationalisation of the sugar industry, firstly are you going to take prompt steps to bring about nationalisation? If you are not going to do that, is it not a fact that keeping the issue pending acts as a further incentive to the factories in not paying the proper price to the sugar cane growers? Therefore, once for all, will you please take a final decision?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: The question of nationalisation is a very much larger subject and the Government have to give it a very careful consideration.....

SHRI INDRAJIT GUPTA: How many years will they give it careful consideration?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: Considering the fact that this time we feel that the export of sugar and earning of as much foreign exchange as we can is very very important, we do not wish to do anything...

PROF. MADHU DANDAVATE: He is misguiding. Exports have nothing to do with nationalisation.

SHRI AMRIT NAHATA: Even after nationalisation exports may go up.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: We are fully alive to the need for ensuring proper payment to the farmers. The Government has taken various steps in this regard. We have issued instructions to the commercial banks to ensure that on the advances that they give to the sugar mills the first charge should be payment for the sugar cane. That is why in UP this year the payments are current and that there are no arrears for the present year.

PROF. MADHU DANDAVATE: We seek your protection. This question was posed on a number of occassions and the Government does not give a straightforward answer at all. You should protect all of us - from both sides of the House. This question was repeatedly asked and every time they say that they will take a proper decision at the proper time and that the matter will take time.

MR. SPEAKER: I can protect you only if you give me the decision making power.

श्री रामचन्द्र विकल : अध्यक्ष जी, गन्ने वाले मूल्य पर मंत्री जी का सन्तोषजनक उत्तर नहीं आया । आप इस पर विवाद का मौका दें क्योंकि यू० पी० और बिहार में काफी किसानों का बकाया चीनी मिलों पर है। इस लिये मेरा आप से अनुरोध है कि आप इस पर विवाद करायें ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो थोड़े देर मंत्री का तजुर्बा कर आये हैं यू० पी० में । आप कृपया बैठिये ।

Slow progress of Irrigation in Maharashtra

*468. SHRI SHANKERRAO SAVANT: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) how much land in Maharashtra was irrigated by surface irrigation during 1972-73, 1973-74 and 1974-75;

(b) what are the reasons for the slow progress of irrigation in that State; and

(c) what attempts are made or are in contemplation to increase the flow irrigation in that State?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI KEDAR NATH SINGH): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The area irrigated in Maharashtra by surface irrigation excluding areas by tanks serving less than 250 acres during 1972-73 and 1973-74 in the State Sector was as under —

1972-73		4.31 lakh ha
1973-74	..	5.23 lakh ha.

Figures of area irrigated during 1974-75 are not yet available.

(a) The area irrigated in Maha-irrigation potential has been satisfactory because the State is investing large sums in irrigation sector. The State Government contemplates to double the outlay on irrigation in the 5th Five Year Plan. The irrigation potential that is planned to be created in the State by major and medium schemes during the 5th Plan is 5 15 lakh hectares compared to 2.78 lakh hectares developed in the Fourth Five Year Plan.

The Maharashtra Government have also set up Command Area Development Authorities for several major irrigation projects for accelerating utilisation of the irrigation potential created.

SHRI SHANKERRAO SAVANT: Before I put any supplementary I should like to have some clarification because there is some confusion in the figures. The statement says that the potential to be created in the 5th Plan is 5 15 lakh hectares while in the statement it is given that in 1973-74 alone 5.23 lakh hectares have already been irrigated. The statement further says that 2.73 lakh hectares have been irrigated in the